

being utilised at Pophali and Koyana Stage-III Power Houses, and if these waters are to be re-used, these will have to be lifted through substantial height involving huge costs.

(c) The Government of Maharashtra have informed that the permitted diversion of waters for power generation from Koyana Project is 1911 million cubic metres and the present requirement of water for Bombay City for domestic and industrial use is around 1359 million cubic metres.

(d) The Government of Maharashtra have reported that the Master Plan for water resources development in Konkan districts have been drawn up and that it is possible to meet the requirements by the water resources available in the Konkan districts only by flow or with small lifts. They are therefore, of the opinion that question of large scale lifting of Koyana tail waters does not arise immediately.

#### Setting up of National Fisheries Development Board

36. SHRIMATI SANYOGITA RANE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the All India Marine Fish Marketing Study conducted by the Indian Institute of Management had made recommendation for setting up a National Fisheries Development Board;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the decision taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) A study on the marine fish marketing under the World Bank Project was entrusted to the Indian Institute of Management, Ahmedabad. They have not yet submitted their report.

(b) and (c). Does not arise.

#### Panel for Rural Employment

37. SHRI CHITTA MAHATA: Will the Minister of RURAL RECONSTRUCTION be pleased to state:

(a) whether Government have asked a panel to submit its report for rural employment; and

(b) if so, the terms and conditions of the panel?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BALESHWAR RAM): (a) and (b). The question of forming a committee in connection with rural employment is under consideration of Central Government.

#### दिल्ली पुनर्वासि बस्तियों का विकास

38. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे:

श्री सज्जन कुमार:

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में पुनर्वासि बस्तियों के विकास पर मार्च, 1979 से लेकर दिसम्बर 1979 तक कितनी धन राशि खर्च की गई;

(ख) इन बस्तियों के विकास पर जनवरी, 1979 से मार्च, 1981 तक मदवार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) इन बस्तियों के विकास पर 1981-82 में किये जाने वाले खर्च का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसने इस अवधि

के दौरान झुग्गी झोंपड़ी हटाओं योजना पर 60.41 लाख रुपये का व्यय किया था ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसने इस अवधि के दौरान झुग्गी झोंपड़ी हटाओं योजना पर 14.97 करोड़ रुपये का व्यय किया था, जिन मदों पर व्यय किया गया है वे विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1981-82 के लिए अपने बजट अनुमान में 11.38 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान किया है जिसका व्यौरा निम्न प्रकार है :—

प्रशासन :	0.24 करोड़ रुपये
भूमि के लागत सहित	
जे०जे० कालोनियों	
में सुधार योजनाएं :	1.90 करोड़ रुपये
जे०जे० कालोनियों में	
अतिरिक्त सुविधाएं :	5.93 करोड़ रुपये
अनुरक्षण :	1.87 करोड़ रुपये
सफाई :	1.44 करोड़ रुपये
	<hr/>
जोड़	11.38 करोड़ रुपये
	<hr/>

**विवरण**

**कार्य की मदें**

1. सड़कों मार्गों तथा बीधियों के निर्माण/सुधार तथा मरम्मत ।
2. नालियों का निर्माण/सुधार तथा मरम्मत ।
3. नई जलपूर्ति योजनाओं, नलकूपों, जलपूर्ति लाइनों की मरम्मत करने तथा निष्ठाने, हैण्ड पम्प आदि के व्यय को शामिल करके जलपूर्ति ।

4. सीवर तथा शौचालय ब्लॉक और मूत्रालयों जिनमें अतिरिक्त शौचालय सीटों का निर्माण शामिल है, सीवर लाइनों का बिछाना, शौचालयों ब्लॉकों में सुधार परदा दीवारों आदि का निर्माण ।

5. अतिरिक्त सुविधायें जैसे समाज सदन टी० वी० केन्द्र, बरात घर आदि ।

6. सफाई, सफाई संयंत्रों, जलपूर्ति तथा नागरिक कार्यों का वार्षिक/रोजमर्रा के अनुरक्षण तथा मरम्मत ।

7. विद्युतीकरण/गली प्रकाश ।

8. नए प्लाटों का विकास ।

9. विधि/अन्य व्यय ।

**Fall in Unloading of Foodgrains in West Bengal**

39. SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware about the drastic fall in the rate of unloading foodgrain from wagons at different railway sidings in the Howrah and Sealdah divisions by the Food Corporation of India in recent months; and

(b) what action has been taken by the Government against the Food Corporation of India stating details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) Yes, Sir. Because of comfortable stock position of foodgrains with the Food Corporation of India in West Bengal, as also to suit the Food Corporation of India handling capacity at various